

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 16 मार्च, 2016

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शहरी विकास विभाग हेतु की गयी घोषणा सं0 676/2014 के क्रियान्वयन हेतु पुनरीक्षित आगणन पर स्वीकृति एवं ₹100.39 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1444/XXVII(1)/2015 दिनांक 14.12.2015 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय, अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 08/XXXV-4/2016 दिनांक 05.01.2016 के अनुक्रम में स्वीकृत ₹20.00 करोड़ के सापेक्ष मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या 676/2014, के अनुपालन में "नरेन्द्रनगर में सामुदायिक विकास भवन के अवशेष निर्माण कार्य" हेतु गठित एवं लोक निर्माण विभाग की विभागीय टी0ए0सी0 में संस्तुत पुनरीक्षित आगणन लागत ₹170.99 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में शासनादेश संख्या 254/V- श0वि0-06-247-(सामान्य)/2005, दिनांक 06.02.2006 के द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹70.60 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि ₹ 100.39 लाख (रूपये एक करोड़ उन्तालीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित कर निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन (जिलाधिकारी, टिहरी-4217) पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- I. जिलाधिकारी, टिहरी द्वारा कुल ₹ 100.39 लाख (रूपये एक करोड़ उन्तालीस हजार मात्र) आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन कार्यदायी संस्था (लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर) को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
- II. आकस्मिकता निधि से उपर्युक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक आय-व्ययक अथवा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से संगत योजना की मानक मद में धनराशि की व्यवस्था कराते हुए प्राप्त होने वाली धनराशि द्वारा यथासमय कर ली जायेगी।
- III. कार्य की प्रगति की निरंतर एवं गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- IV. उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008, दिनांक: 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- V. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- VI. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में किया जायेगा।
- VII. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-400/XXVII(1)/2015 दिनांक: 13अप्रैल, 2015 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- VIII. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IX. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

- X. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- XI. उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हों।
- XII. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- XIII. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- XIV. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य कराया जाय।
- XV. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- XVI. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- XVII. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
- XVIII. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- XIX. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त सामग्री का प्रयोग उपयोग में लायी जाए।
- XX. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- XXI. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुसूक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
- XXII. उक्त कार्य के आगणन पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने से पूर्व प्रशासकीय विभाग यह भी सुनिश्चित कर लें कि यदि शासनादेश संख्या-571/XXVII(1)/2010, दिनांक 19.10.2010 के दिशा-निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तो प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में बचत है तो उसे द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित कर लिया जाए।
- XXIII. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। यदि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय संख्या 08/XXXV-4/2016 दिनांक 05.01.2016 के अनुक्रम में स्वीकृत ₹20.00 करोड़ प्राविधानित व्यवस्था के सापेक्ष प्रथमतः लेखाशीर्षक-8000-आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि-लेखा-201 समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या-3 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य भवन, 800-अन्य व्यय, 02-माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0सं0-178 (P)/XXVII(5)/2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

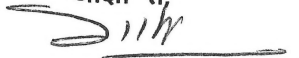
सचिव।

संख्या- 132/XXXV-4/16/31(मु0मं0घो0)14तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, (लेखा एवं हकदारी) ओवराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. अनु सचिव (लेखा) आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।
12. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
13. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर (टिहरी)।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर।
15. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,



(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, CM Ghoshna (Grants) (9007)

आवंटन पत्र संख्या - 132/xxxv-4/16/31(cmgho)14

अनुदान संख्या - PAC

अलोटमेंट आई डी - F160399005X

आवंटन पत्र दिनांक - 16-Mar-2016

लेखा शीर्षक - 8000-00-201-00-00 (राज्य आकस्मिकता निधि)

Name - District Magistrate (For Grants)Tehri (4183) , Treasury - New Tehri (6100)

1: लेखा शीर्षक	4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	60 - अन्य भवन
जिसमें	800 - अन्य व्यय	
समायोजन होना	00 - k	02 - मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अन
		(अनुदान संख्या - 00

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Plan Voted
24 - ग्रहण निर्माण कार्य	0	13900000	योग
	0	13900000	13900000
		13900000	13900000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

13900000